

# **Press Clippings**

28<sup>th</sup> December, 2017

**MoU signed between Forest  
Research Institute,  
Dehradun & Department of  
Land Resources, Minister of  
Rural Development, New  
Delhi  
on  
27<sup>th</sup> December, 2017**

## THE HAWK

### 28-12-2017

# MoU Signed Between Forest Research Institute And Department Of Land Resources, Ministry Of Rural Development, New Delhi

**Dehradun:** A Memorandum of Understanding (MoU) was signed today on 27th December, 2017 in the Chamber of Director, Forest Research Institute, Govt. of India and Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, New Delhi.

The MoU was signed by Dr. Savita, Director FRI and Mr. Amit Kumar, Director (Watershed Management).

Dr. Savita informed that this MoU is for a period of 5 years. The main objective of the assignment is to support the Neeranchal PIU to achieve results pertaining to Capacity building at the central level and at State level. FRI will develop training content module for imparting training on Watershed management and allied field for the personnel's of Neeranchal project.

Training module will be of officers, staff and local people. The project will focus on supporting watershed management training

in the following nine States: Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Odisha, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra Rajasthan and Telangana. The project cost is Rs. 4.99 crore.

---



## राष्ट्रीय सहारा

28.12.2017

### 499 करोड़ की परियोजना पर एमओयू

देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई) व ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन प्रभाग के मध्य एक समझौता ज्ञापन हुआ है। बुधवार को एफ.आर.आई की निदेशक डा. सविता व वाटरशेड मैनेजमेंट के निदेशक अमित कुमार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये। यह एमओयू पांच साल के लिए हुआ है। डा. सविता ने बताया कि इस कार्य का मुख्य उद्देश्य नीरांचल परियोजना में शामिल राज्यों के अधिकारी, कर्मचारी व जनमानस की प्रशिक्षण जरूरतों का आकलन व प्रशिक्षण कार्यक्रम का मॉड्यूल बनाना है। साथ ही विभिन्न संस्थानों का चिन्हीकरण और इन संस्थानों द्वारा परियोजना में शामिल राज्यों के विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण मुहैया कराना है। परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान व तेलंगाना में जल विभाजन प्रबंधन कार्यकलापों में सुधार लाना है। परियोजना की लागत 499 करोड़ है।



हिन्दुस्तान

28.12.2017

## नीरांचल प्रोजेक्ट के लिए एमओयू

देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान यानी एफआरआई और केंद्रीय भूमि संसाधन प्रभाग मिलकर नौ राज्यों में जल विभाजन प्रबंधन के लिए काम करेंगे। बुधवार को एफआरआई में दोनों के बीच नीरांचल परियोजना को लेकर एमओयू हुआ।

एफआरआई पांच साल के समझौते के तहत नीरांचल में शामिल राज्यों के अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा लोगों को भी जल प्रबंधन का प्रशिक्षण देगा। एफआरआई निदेशक डॉ. सविता और वाटरशेड मैनेजमेंट के निदेशक अमित कुमार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। डॉ. सविता ने बताया कि इसका उद्देश्य ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करना है। साथ ही विभिन्न संस्थानों का चिन्हीकरण भी होगा। इसके तहत आंध्रप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना फोकस रहेगा।

दैनिक जागरण

28.12.2017

## एफआरआई ने किए एमओयू पर हस्ताक्षर

देहरादून: वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) और ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन प्रभाग ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

बुधवार को एमओयू एफआरआई की निदेशक डॉ. सविता व निदेशक जलागम प्रबंधन अमित कुमार ने हस्ताक्षर किए। डॉ. सविता ने एमओयू के संबंध में जानकारी दी कि यह समझौता पांच वर्ष के लिए है। इस अवधि में निरांचल परियोजना में सम्मिलित राज्यों के कार्मिकों व जनमानस की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण का मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। परियोजना की लागत 4.99 करोड़ रुपये है।

अमर उजाला

28.12.2017

## एफआरआई और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच एमओयू

देहरादून। चार राज्यों के बीच जल विभाजन प्रबंधन की गतिविधियों को संचालित करने और बेहतर कार्ययोजना तैयार करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान और भूमि संसाधन प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के मध्य बुधवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर एफआरआई की निदेशक डॉ. सविता और निदेशक वॉटरशेड मैनेजमेंट अमित कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर निदेशक डॉ. सविता ने बताया कि यह समझौता ज्ञापन पांच वर्ष के लिए है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य निरांचल परियोजना में सम्मिलित राज्यों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा जनमानस को प्रशिक्षण देना है।

शाह टाइम्स

27.12.2017

## कर्मचारियों के प्रशिक्षण को एफआरआई का करार

ग्रामीण विकास मंत्रालय  
के साथ हुआ समझौता

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान एवं भूमि संसाधन प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के बीच एक करार (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर वन अनुसंधान संस्थान की ओर से निदेशक वन अनुसंधान संस्थान डा. सविता, निदेशक वाटरशेड मैनेजमेंट अमित कुमार ने हस्ताक्षर किए।

निदेशक वन अनुसंधान संस्थान डा. सविता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह समझौता पांच वर्ष के लिए है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य नीरांचल परियोजना में शामिल राज्यों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा जनमानस की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन एवं



प्रशिक्षण कार्यक्रम का मोड्यूल बनाना तथा विभिन्न संस्थानों का चिन्हीकरण एवं उन संस्थानों द्वारा परियोजना में शामिल राज्यों के विभिन्न स्तर के कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराना है। इस परियोजना के अंतर्गत आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तेलंगाना नौ राज्यों में जल विभाजन प्रबंधन कार्यकलापों पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। इस परियोजना की लागत 4.99 करोड़ रुपये है।

## THE PIONEER

28-12-2017

### MoU signed between Forest res inst and Land Resou dept

PNS ■ DEHRADUN

A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the Forest Research Institute and the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, here on Wednesday. The MoU was signed by FRI director Savita and Watershed Management director Amit Kumar. The FRI director informed that the main aim of the MoU which is for a period of five years, is to support the Neeranchal PIU to achieve results pertaining to capacity building at the central level and at state level. FRI will develop training content module for imparting training on watershed management and allied field for the personnel of Neeranchal project. Training module will be for officers, staff and local people. The project will focus on supporting watershed management training in the nine States of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Odisha, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Telangana. The project cost is ₹ 4.99 crore.



# FRI signs MoU with Department of Land Resources

DEHRADUN,  
DEC 27 (HTNS)

**A** Memorandum of Understanding (MoU) was signed in the Chamber of Director, Forest Research Institute, Govt. of India and Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, New Delhi here today.

The MoU was signed by Dr. Savita, Director FRI and Amit Kumar, Director (Watershed Management).

Dr. Savita informed that this MoU is for a period of 5 years. The main objective of the assignment is to support the Neeranchal PIU to achieve results pertaining to Capacity Building at the central level and at State level. FRI will develop training content module for imparting training on Watershed Management and al-



lied field for the personnel's of Neeranchal project. Training module will be of officers, staff and local people. The project will fo-

cus on supporting watershed management training in the following nine States: Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat,

Odisha, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Telangana. The project cost is Rs. 4.99 crore.



उत्तराखण्ड केसरी

28.12.2017

## एफ.आर.आई. ने किया एम.ओ.यू. साइन

देहरादून, 27 दिसम्बर (स.ह.): वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक कक्ष में वन अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान में भूमि संसाधन प्रभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर वन अनुसंधान संस्थान की ओर से डा. सविता, निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान तथा अमित कुमार, निदेशक, वाटरशेड मैनेजमेंट ने हस्ताक्षर किए। डा. सविता, निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह समझौता 5 वर्ष के लिए है।

इस कार्य का मुख्य उद्देश्य नीरांचल परियोजना में सम्मिलित राज्यों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा जनमानस की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का



कार्यक्रम का दृश्य (अमित)

आंकलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का मॉड्यूल बनाना तथा विभिन्न संस्थानों का चिन्हीकरण एवं उन संस्थानों द्वारा परियोजना में शामिल राज्यों के विभिन्न स्तर के कर्मचारियों का प्रशिक्षण करवाना है। इस परियोजना के अंतर्गत

आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तेलंगाना 9 राज्यों में जल विभाजन प्रबंधन कार्यकलापों पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। इस परियोजना की लागत 4.99 करोड़ रुपए है।

जनभारत मेल

28 12.2017

## एफआरआई और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच हुआ एमओयू

देहरादून। बुधवार को वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक कक्ष में वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून एवं भूमि संसाधन प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर वन



अनुसंधान संस्थान की ओर से डा. सविता, निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान तथा अमित कुमार, निदेशक, वाटरशेड मैनेजमेंट ने हस्ताक्षर किए। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य नीरांचल परियोजना में सम्मिलित राज्यों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा जनमानस की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का मोडयूल बनाना तथा विभिन्न संस्थानों का चिन्हीकरण एवं उन संस्थानों द्वारा परियोजना में शामिल राज्यों के विभिन्न स्तर के कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराना है। इस परियोजना के अंतर्गत आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तेलंगाना नौ राज्यों में जल विभाजन प्रबंधन कार्यकलापों पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा।